

**MESSAGE FROM THE LOK SABHA  
The Essential Commodities (Amendment)  
Bill, 1998**

SECRETARY-GENERAL: Mr. Chairman, Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Thursday, the 9th July, 1998, adopted the enclosed motion in regard to the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1998.

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the Members of Rajya Sabha appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House.

**MOTION**

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members, 20 from this House, namely:—

1. Shri Amrik Singh Aliwal
  2. Shri N. Dennis
  3. Shri Abdul Ghafoor
  4. Shri Satya Pal Jain
  5. Shri Shanker Prasad Jaiswal
  6. Shri Bhubaneswar Kalita
  7. Shri Vijay Kumar Khandelwal
  8. Prof. Ajit Kumar Mehta
  9. Shri Shyam Bihari Mishra
  10. Shri S. Murugesan
  11. Shri Ajit Kumar Panja
  12. Shri Harin Pathak
  13. Smt. Suryakanta Patil
  14. Prof. A.K. Premajam
  15. Shri Malyala Rajaiah
  16. Shri Konijeti Rosaiah
  17. Shri Kishan Singh Sangwan
  18. Shri Mohan Singh
  19. Shri K.D. Sultanpuri
  20. Shri Braja Kishore Tripathi
- and 10 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be

one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 10 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee".

**RE: POSTAL STRIKE**

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, taking advantage of the presence of the Prime Minister in the House, I would like to draw the attention of the House and the Prime Minister to the nation-wide postal strike....

MR. CHAIRMAN: That issue was raised yesterday. (*Interruptions*). That issue was raised yesterday.

SHRI NILOTPAL BASU: What is the Government doing to solve this problem? (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: That matter was raised yesterday. Please sit down. (*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: The postal employees are agitating throughout the country...(*Interruptions*) Sir, it is a very serious issue. (*Interruption*).

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, I also raised this matter four days back. (*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: Sir,... (*Interruptions*).

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: The Postal Department is completely paralysed. I raised this issue four days back. There is no response from the Government. Yesterday, Shri Vayalar Ravi also raised this issue. But there is

no response from the Government. Let : them have a dialogue with the leaders... (Interruptions).

SHRI NILOTPAL BASU: Let the Government respond. (Interruptions).

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Discussion has been going on at different levels. (Interruptions).

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): What steps has the Government taken to settle this matter? (Interruptions). I request the Prime Minister to make a statement. (Interruptions). What steps is the Government taking to settle this issue? (Interruptions).

श्री नरेश यादव (बिहार) : आखिर सरकार क्या कर रही है। इस बारे में .....(व्यवधान)

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : कर्मचारियों की हड़ताल से पूरे देश को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है .....(व्यवधान) सारे देशवासी कठिनाई में हैं .....(व्यवधान)

SHRI NILOTPAL BASU: Will the Government negotiate with them or not? (Interruptions). We would like to know whether the Government will negotiate or not. (Interruptions).

श्री दीपाकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : यह चिट्ठी की बात है, चिट्ठी, चिट्ठी। एक चिट्ठी के लिए चक्कर हो रहा है .....(व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु : इसके चलते तो सरकार भी जा सकती है। .....(व्यवधान)

SHRI NILOTPAL BASU: I would like to know whether the Government will negotiate or not. The entire postal activities have come to a standstill. It is not a small thing... (Interruptions)

श्रीमती कमला सिन्हा : प्रधान मंत्री जी को कुछ इस पर भी कमेंट करने को बोलिए। .....(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति जी, सरकार और डाक कर्मचारियों के बीच में वार्ता चल रही थी। यह ठीक है, कि कर्मचारियों ने जो रवैया अपनाया था वह समझौते में सहायक नहीं था। लेकिन सरकार समझौता करना चाहती थी। अभी भी बातचीत चल रही है और कोई न कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ।

## DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS contd.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय पर हुई लम्बी बहस का उत्तर सचमुच में इस बात का परिचायक है कि माननीय सदस्य विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और यह आवश्यक भी है। हमारे देश में विदेश नीति पर हमेशा एक आम सहमति रही है। इसका अर्थ यह नहीं है। कि समय-समय पर कुछ मतभेद नहीं उभरे लेकिन भारत की विदेश नीति स्वतंत्र हो, स्वावलम्बन को बढ़ावा दें, भारत के हितों की रक्षा करने में समर्थ हो और विश्व के शांति स्थापना में योगदान दें, यह प्रारम्भ से विदेश नीति का लक्ष्य रहा है। इसको लेकर एक आम सहमति रही है। जब यह कहा जाता है कि आम सहमति टूट गई है तो मेरा निवेदन है कि स्थिति के साथ सही न्याय नहीं किया जाता। हमारी विदेश नीति के साथ सही न्याय नहीं किया जाता। हमारी विदेश नीति के अन्तर्गत सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की बात है, यह सम्बन्ध अभी तक स्थापित रहे हैं। जब से इस सरकार ने कार्यभार संभाला है। इन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़े हैं। हमारे राष्ट्रपति जी अभी नेपाल की सफल यात्रा करके आए हैं। बंगला देश की प्रधान मंत्री थोड़े दिन पहले दिल्ली में आई थी और उनसे बड़े मैत्रीपूर्ण वातावरण में, सहयोग के वातावरण में चर्चा हुई। मालदीव्स के राष्ट्रपति रहे हैं। अब कोलम्बो में वह दूसरे को कार्यभार सौंपेगे। उनसे भी बड़ी अंतरंग बातचीत हुई। हमारे विदेश सचिव सभी बंगला देश गए थे, वह भूटान की यात्रा भी करके आए हैं। तो यह कहना कि भारत अलग-अलग पड़ गया है यह न्याय करना नहीं है। हां, पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएं हैं। हमारी तरफ से लगातार यह कोशिश होती रही है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य हों और सामान्य संबंध मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलें, आर्थिक सहयोग के लिए नए दरवाजे खुले, लोगों के आने-जाने में आसानी हो लेकिन इस संबंध में पाकिस्तान से जितना सहयोग मिलना चाहिय था, नहीं मिला है। पाकिस्तान से वार्ता चल रही थी जब पुरानी सरकार थी। ढाका में एक फार्मुला भी तैयार हुआ था जिसके अनुसार बातचीत का क्रम तय होना था लेकिन सात-आठ महीने पाकिस्तान ने अपनी सहमति नहीं दी। इसके साथ ही देश के भीतर ऐसी विरोधी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास हुआ जिनसे कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो।